सबसे बड़ी गलती कांग्रेस कर रही है, चौटाला परिवार भी छिप गया है कहीं.....

पेज एक का शेष

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गणित

लोकसभा चुनाव हारने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने समर्थक विधायकों, नेताओं और चुनिंदा कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में आए हुए सभी विधायकों और नेताओं से यह जानकारी ली कि अगर हुड्डा कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उस स्थिति में हालात क्या होंगे और जनता साथ देगी या नहीं। विधायकों और नेताओं से यह भी पूछा गया कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद अपने सभी समर्थकों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो जाएं तो क्या स्थिति रहेगी। ज्यादातर विधायकों और नेताओं ने हुड्डा को दोनों ही विकल्प में से किसी एक के भी चुनने पर असहमति जता दी। इसके बाद हुड्डा और उनके कुछ चुनिंदा नेताओं ने हरियाणा की राजनीति पर पकड़ रखने वाले पत्रकारों और बुद्धिजीवियों से भी इन्हीं विकल्पों पर राय मांगी। इन लोगों ने भी हुड्डा को इन दोनों ही विकल्पों में से किसी एक भी पर विचार नहीं करने को कहा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि हुड्डा इन गतिविधियों के जरिए कांग्रेस आलाकमान को भी संदेश देना चाहते थे। संदेश तो गया लेकिन उसका असर नजर आया। इससे पहले कुलदीप विश्नोई और उससे कई और नेता ऐसे टोटके आजमा चुके हैं लेकिन उन्हें लौटकर वापस कांग्रेस में आना पड़ा। हुड्डा का यह दांव खाली चला गया।

हुड्डा की मुश्किल और कांग्रेस आलाकमान का बेवकूफाना रवैया

कांग्रेस आलाकमान और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इर्दगिर्द रणदीप सुरजेवाला का इतना मजबूत घेरा है कि कांग्रेस आलाकमान हुड्डा को हरियाणा की कमान सौंपने को तैयार नहीं है। रणदीप जींद उपचुनाव बुरी तरह हार गए

इसके बावजूद आलाकमान हरियाणा के बारे में कोई भी फैसला बिना रणदीप की सलाह लिए नहीं कर रहा है। कांग्रेस यह भी कर सकती थी कि रणदीप पर वह हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी देकर हुड्डा को राष्ट्रीय राजनीति में बुला लेती। लेकिन उसने हुड्डा को लेकर अभी तक पसोपेश बरकरार रखा हुआ है। हरियाणा में जाट राजनीति के लिए हुड्डा और रणदीप में से किसी एक को कांग्रेस आलाकमान को चुनना पड़ेगा। रणदीप के मुकाबले हुड्डा की स्थिति जाट राजनीति में अभी भी ठीकठाक है। बेशक जाटों ने कांग्रेस से दगाबाजी कर लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट डाले लेकिन विधानसभा में स्थितियां विपरीत हैं। हुड्डा के प्रभाव से कांग्रेस जाट बेल्ट में कुछ सीटें तो निकाल ही सकती है। अभी आलाकमान ने जो हालात बना दिए हैं, उसमें भाजपा को वॉकओवर मिल रहा है। जाट बेल्ट में इस समय भाजपा का एकमात्र काम जेजेपी और कांग्रेस के मजबूत लोकल नेताओं को तोड़कर भाजपा में लाना है। रोहतक, भिवानी, जींद, झज्जर, हिसार और सोनीपत से कई दमदार स्थानीय नेता भाजपा अपने कैंप में ला चुकी है। जाट बेल्ट की इन सभी सीटों पर भाजपा को अगर कोई प्रभावशाली चुनौती अगर दे सकता है तो वह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस ही है।

हुड्डा की मुश्किल यह है कि वह न तो कांग्रेस छोड़कर जा पा रहे हैं और बेवकूफ कांग्रेस आलाकमान उन्हें लेकर फैसला भी नहीं कर पा रहा है। हुड्डा ने पार्टी छोड़ने के विकल्प पर जानकारी जुटा ली लेकिन अगर उनके समर्थक उनके साथ कांग्रेस से नहीं निकले तो उनकी फजीहत होना तय है। ऐसे में हुड्डा के सामने भी बड़ा धर्मसंकट बना हुआ है। बहरहाल, इस कन्फ्यूजन का फायदा भाजपा पूरी तरह उठाने को तैयार है।

आखिर अशोक तंवर क्या चाहता है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को राहुल गांधी ने अपना सिपहसालार बनाकर इसलिए उतारा था कि यह शख्स हरियाणा में कांग्रेस की साफ सुथरी राजनीति करेगा और हुड्डा को भी काबू रखेगा। तंवर ने राहुल गांधी के दूसरे वाले संदेश पर खूब अमल किया लेकिन पार्टी को जमीन पर नहीं खड़ा कर सका। पिछले लोकसभा चुनाव में दूर-दूर तक कांग्रेस का कोई भी बूथ मैनेजमेंट अशोक तंवर के नेतृत्व में नजर नहीं आया। पार्टी आलाकमान ने इसे सिरसा से लोकसभा का टिकट देकर इसका दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। नतीजा यह निकला कि तंवर सिर्फ सिरसा लोकसभा चुनाव में अपना बूथ मैनेजमेंट तो करता रहा लेकिन शेष हरियाणा को भूल गया। यह शख्स कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हर दिन नई पैंतरेबाजी करता है। इसने 5 जुलाई को घोषणा की कि 8 जुलाई को दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन और मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी। इस कमेटी का सदस्य बनने के लिए हुड्डा के अलावा किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप विश्नोई को भी निमंत्रण भेजा गया। इन लोगों से यह भी कहा गया कि वे लोग अगर ना आ सकें तो अपने प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं।

अशोक तंवर का बुलाने का अंदाज ऐसा है कि शायद ही कोई पहुंचे। कायदे से तो अब तक अशोक तंवर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था लेकिन उसने आला कमान से अनुमति लिए बिना एक और कमेटी बनाने के लिए बैठक बुला ली। हालांकि उसका कहना है कि 8 जुलाई की बैठक के लिए आला कमान की अनुमति ली गई है लेकिन इस समय कांग्रेस आलाकमान नाम की चीज काम ही नहीं कर रही है तो तंवर ने किससे अनुमति ली कोई नहीं जानता। दरअसल, तंवर ने अपनी चालाकी से यह बैठक रखी है। इसके बाद उसका अगला कदम टिकट के लिए नाम तय करना है।

क्या मुद्दे खत्म हो गए विपक्ष के लिए

हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार रोजाना नए गुल खिला रही है लेकिन जेजेपी और इनैलो का कोई आंदोलन नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की बात ऊपर हो चुकी है, वह पार्टी जबरदस्त गुटबाजी का शिकार है।

उससे किसी भी तरह के आंदोलन की उम्मीद नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव हारने के बाद जेजेपी और इनैलो ने खुद को हाशिए पर हुआ मान लिया है। लोकसभा चुनाव में हर सीट पर जेजेपी को इनैलो के मुकाबले ठीकठाक वोट मिले हैं। उसकी संभावनाएं राज्य की राजनीति में अभी भी बनी हुई हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जेजेपी के दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने अपनी सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद कर दी हैं। अगर चौटाला परिवार में समझौते की खिचड़ी पक रही है और दोनों भाई (अजय-अभय) एक हो रहे हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। अगर यह स्थिति बनी तो यह लोग कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को ज्यादा बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। परिवार की एकता के लिए बस जुलाई का ही महीना बचा है।

अक्टूबर में चुनाव की पूरी संभावना है। इस तरह सारे चुनावी प्रपंच के लिए दो महीने मिलेंगे। भाजपा के अलावा किसी की चुनावी तैयारी नहीं है। ऐसे में जुलाई का महीना विपक्ष की सारी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आखिरी मौका है। वरना विपक्ष का राम-नाम सत्य हो जाएगा और भाजपा आसानी से फिर सरकार बना लेगी।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मोदी द्वारा भारत को विश्वगुरू बताने पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की उपहास भरी टिप्पणी

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

जबसे केन्द्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से देश में आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनायें हो रही है। गौ-हत्या गौ-तस्करी व लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों व दलितों को मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी रस्मी तौर पर मॉब लिंचिंग की आलोचना तो करते हैं परन्तु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद इसकी रोक-थाम के लिये धरातल पर कोई ठोस कार्यवाई नहीं की। झारखंड के खरसावां सरायकला ज़िले में मोटर साइकिल की चोरी के शक पर तरबेज को खंभे से बांधकर 13 घंटे तक पीटा जिसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। भीड़ द्वारा उसे 'जय श्री राम' व 'जय हनुमान' बोलने को कहने पर तरबेज द्वारा इन नारों को बोलने पर भी उसे छुटकारा नहीं मिला। इस दर्दनाक अमानवीय घटना के संदर्भ में 'हत्यारों का संबल है अब राम तुम्हारा नाम। हत्यारों के काम आ रहा राम तुम्हारा नाम।।', 'प्रशासन एक भीड़' तथा 'हमको कभी माफ़ मत करना, तबरेज़...' के जरिए प्रशासन, न्याय प्रणाली व पुलिस विभाग की लापरवाही, संवेदनहीनता व असफलता की समीक्षा की गई है। पूरी भीड़ का हत्यारा हो जाना सभ्य व प्रजातांत्रिक समाज के चेहरे पर काला धब्बा है। आश्चर्य है कि दो साल पहले अलवर में गौ रक्षकों की पिटाई में मारे गए पहलू खान को राजस्थान कांग्रेस सरकार की पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट में पहलू को गौ तस्कर बताया है तो उसके दो बेटों और टैंपो आपरेटर को आरोपी बनाया है।

मज़दूर मोर्चा के 30 जून-6 जुलाई 2019 के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार प्रकाशित हुए हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25-26 जून 2019 को देश में आंतरिक आपातकाल घोषित किया था, जिसे भारतीय प्रजातांत्रिक राजनीति में काले दिनों के रूप में याद किया जाता है। इस समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को प्रतिबंधित कर दिया गया और अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपातकाल की 44 वीं वर्षगांठ पर आरएसएस (संघ), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मोदी सरकार तथा मीडिया ने आपातकाल के लिये कांग्रेस की कटु आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इमरजेंसी संविधान को कुचलने का पाप है। यह दाग नहीं मिटेगा। किसी की सत्ता बचाने के लिये देश को जेल खाना बना दिया गया। विडम्बना है कि किसी ने भी संघ व तत्कालीन सरसंघचालक वाला साहब देवरस की इस दौरान निभाई गई भूमिका की कोई चर्चा नहीं की।

संघ सदैव दावा करता रहा कि उसने आपातकाल का बहादुरी से मुकाबला लिया और भारी दमन का सामना किया। लेकिन 'भारत में आपातकाल की 44 वीं वर्षगांठ: आपातकाल विरोधी आंदोलन से आरएसएस की गहरी' तथा 'आपातकाल के दौरान आरएसएस ने आखिर क्यों मांगी थी इंदिरा गांधी से माफ़ी!' में उद्धृत कथानक व प्रमाणों से संघ के इन झूठे दावों का भांडा-फ़ोड़ किया गया है।

वरिष्ठ पत्रकार और विचारक प्रभात जोशी का अंग्रेजी साप्ताहिक तहलका में प्रकाशित लेख, पूर्व खुफ़िया ब्यूरो (आईबी) प्रमुख टीवी राजेश्वर की पुस्तक 'इंडिया द क्रुशियल इयर्स (हार्पर कॉलिन्स) तथा वॉल्टर के. एंडरसन और संघ से सम्बन्धित श्रीधर डामले द्वारा लिखित पुस्तक 'द ब्रदरहुड इन सैफ्रन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एंड हिंदू रिवाइलिज्म' में उल्लिखित तथ्यों व आरएसएस अभिलेखागार के समकालीन दस्तावेज़ों से प्रमाणित होता है कि संघ ने इंदिरागांधी के आगे घुटने टेक दिये थे और इंदिरा गांधी व उनके पुत्र संजय गांधी को 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने के रूप में माफ़िनामे पर हस्ताक्षर कर जेल से छूटे थे। उनके नेता लोग ही जेल में रह गए थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, अरूण जेटली आदि। इन सबके बावजूद संघ से सम्बन्धित लोग आपातकाल के दौरान उत्पीड़न के नाम पर आज मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

गौरतलब है कि देवरस इंदिरा गांधी और संजय गांधी से मिलने के इच्छुक थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने इन्कार कर दिया। देवरस ने 22 अगस्त 1975 तथा 10 नवंबर 1975 को इंदिरा गांधी को पत्र लिखे, परंतु इंदिरा गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद देवरस ने आचार्य विनोबा भावे के साथ सम्पर्क साधा और अपने पत्र दिनांक 12 जनवरी 1976 में आग्रह किया कि विनोबा भावे संघ पर से प्रतिबंध हटाने के लिये इंदिरा गांधी को सुझाव दे, परंतु विनोबा भावे ने भी पत्र का जवाब नहीं दिया। हताश देवरस ने इस संबंध में विनोबा भावे को एक और पत्र लिखा।

स्पष्ट है कि संघ सदैव बुनियादी तौर पर समझौतापरस्त रहा है और वह कभी भी सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने वालों में नहीं रहा। इनकी पुरानी रणनीति है कि वह शक्तिशाली शासकों के पक्ष में रहता आया है और निरंकुश शासन का समर्थक रहा है, जिससे वह उनके संरक्षण में अपने नेटवर्क को फ़ैलाता रहे और अनुकूल समय आने पर सत्ता पर काबिज हो जाए। इसलिए संघ के किसी भी नेता अथवा स्वयं सेवक ने देश की आज़ादी के संघर्ष के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कोई शिरकत नहीं की। यही कारण है कि देश की आज़ादी के आंदोलन में जेल में रहने वालों को मिलने वाली स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने वालों में एक भी संघ का स्वयं सेवक नहीं है।

हरियाणा पुलिस व दिल्ली पुलिस ट्रकों व अपराधियों से मंथली वसूल करने में मशगूल रहती है और अपराधी बेखौफ़ होकर चेन-झपट, शराब-तस्करी, नशे, जुए-सट्टे, हत्या आदि आपराधिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। पुलिस वाले अपने उच्चाधिकारियों को मोटी रकम देकर मनमाफ़िक थाने में पोस्टिंग लेते हैं और पोस्टिंग के बाद वे अधिक से अधिक वसूली करते हैं। यह स्थिति केवल दिल्ली व हरियाणा की नहीं बल्कि कमोबेश भाजपा शासित सभी राज्यों की पुलिस की है, जिसका 'दिल्ली पुलिस ही नहीं भाजपा शासित हर राज्य में पुलिस उगाही में आगे-सोचिये, जब देश का गृहमंत्री तड़ीपार हो तो पुलिस रामराज्य स्थापित नहीं करेगी', 'लूट-मार में व्यस्त पुलिस को अपराधियों की चिंता नहीं' तथा 'संत नगर में नशे व जूए के कारोबार को फ़रीदाबाद पुलिस का पूरा संरक्षण-गुंडागर्दी के बल पर अवैध पार्किंग, रेहड़ी-खोखों से वसूली व रेलवे टिकटों का काला बाजारी के जरिए कच्चा चिट्ठा खोला गया है। भाजपा शासित राज्यों में जहां पहले गुंडों का बोलवाला होता था वहां अब पुलिस स्वयं गुंडों की तरह व्यवहार करने लगी है जिस पर नियंत्रण करने में मोदी जी व केन्द्रीय गृह मंत्री अमितशाह गंभीर नहीं लगते।

फ़रीदाबाद व गुड़गांव में अपराधी बेखौफ़ होकर हत्याओं पर उतर आए हैं। उन्होंने बीते सप्ताह फ़रीदाबाद क्षेत्र में एक के बाद एक तीन हत्याएं कर दी मानो कोई मामूली वारदात हो। 27 जून को दिन दहाड़े रिहायशी सैक्टर मार्केट में हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या कर दी गई, जिसकी 'बेतहाशा बढ़ते क्राइम की भेंट चढे कांग्रेस प्रवक्ता विकास चौधरी' तथा 'सुरक्षा के नाम पर भेदभाव' में विवेचना की गई है।

पुलिस की नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिये एडीजी (कानून व्यवस्था) ने बताया कि विकास के खिलाफ़ हरियाणा और यूपी में 2007 से उगाही, अपहरण, हत्या की कोशिश आदि के 13 मामले दर्ज है और हत्या का मामला उनके अपने आपराधिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। जबकि विकास के पिता आरसी चौधरी ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की राजनीतिक हत्या हुई है और पुलिस झूठी कहानी बनाकर हत्या के असली मकसद को छिपा रही है।

विकास की हत्या के मामले में गिरफ़्तार गैंगस्टर कौशल की पत्नी रोशनी और उसके नौकर नरेश उर्फ़ चांद ने बताया कि कौशल का आदेश मिलने पर विकास की हत्या की थी। 'फिरौती का चक्कर' से स्पष्ट है कि इस गैंग ने विकास समेत तीन लोगों से फ़िरौती मांगी थी, जिसे देने से विकास ने मना कर दिया था। पलवल के शराब व्यापारी नारंग से भी एक करोड़ रुपये की फ़िरौती मांगे जाने की चर्चा है। इस प्रकार विकास की हत्या फ़िरौती के चक्कर में की जाने की आशंका है। जिस प्रकार हरियाणा में अंडरवर्ल्ड ने पांव पसारा हुआ है, उससे भाजपा सरकार, पुलिस व न्याय प्रणाली पर सवालिया निशान लगता है।

मोदीजी द्वारा भारत को विश्वगुरू बताने पर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणी पर 'विश्वगुरू संकट क्या है', हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डा.अशोक तंवर के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में कथन पर 'हम विधानसभा की 90 सीटों पर तैयार हैं-तैयार तो भाई तुम लोक सभा की 10 में भी थे, बस तैयार ही होते रहोगे क्या?' नगर निगम अधिकारी द्वारा भिखारी को अठ्ठन्नी देने पर 'भगवान के नाम पर हमें अठ्ठन्नी और खुद भगवान के नाम पर लाखों डकार गए...', लोकसभा में सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण के समय धार्मिक नारे लगाने पर 'जय श्री राम-जै काली-अल्लाह हू अकबर', रोहतक और वडोदरा में बिना उपकरण के सीवर सफाई में चार व सात कर्मी क्रमशः मरने व मोदी द्वारा कुम्भ मेले में पांच दलितों के पैर धोने पर 'वडोदरा में सीवर सफ़ाई में सात लोग मरे-सत्याग्रह-वापस जाओ अपने काम पर अगर अगले चुनाव तक जिंदा रहे तो तुम्हारे पैर भी धुलवा देंगे।' कार्टून द्वारा उपयुक्त तंज कसा गया है।

'बापू निपट गए तो हिन्दू राष्ट्र की पताका फहराना होगा आसान' में मोदीजी की कथनी और करनी में विरोधाभास को उजागर किया गया है। मोदीजी 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' का नारा लगाते हैं लेकिन उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिये कोई ठोस प्रबंध नहीं किये गये तथा बेटियों के बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि ही हुई है। किसानों की आय दुगुनी करने की बात करते हैं लेकिन किसानों द्वारा बदस्तूर आत्महत्या की जा रही है। देश की सुरक्षा के नाम पर सैनिकों की शहादत को भुनाकर लोकसभा तो जीत गए, परन्तु आतंकी हमले अब भी जारी है। आयुष्मान भारत योजना का ढिंढोरा पीटते हैं लेकिन जब बच्चों की मौत की सुनामी आई तो मूक दर्शक बन गए। सबका साथ, सबका विकास तथा सबका विश्वास की बात करते हैं जबकि दलित व अल्पसंख्यकों को शिकार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारी प्रेरणा है जबकि उनकी ही पार्टी की प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को राष्ट्रवादी बताया। जिस पर मोदी जी ने गुस्से में कहा कि वे प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ़ नहीं करेंगे तथा दस दिनों में अनुशासन समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाई होगी। आश्चर्य है कि अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल महात्मा गांधी उनके एजेंडे की सबसे बड़ी बाधा है। बापू प्रेम से उनको निपटा कर 'हिन्दू राष्ट्र' की पताका फ़हराना आसान हो जाएगा।